(1)	(2)	(3)	(4)
C. *SOUTHERN REGION*			
Andhra Pradesh State Electricity Board	5644	1833	7477
Karnataka Electricity Board	1926	1880	3806
Tamil Nadu Electricity Board	5124	3216	8340
Kerala State Electricity Board	3143	1239	4382
Goa	4	—	4
Pondicherry	—156	2	—154
	15685	8170	23855
D. *EASTERN REGION*			
West Bengal State Electricity Board	4498	3337	7835
Bihar State Electricity Board	27898	10650	38540
Orissa State Electricity Board	1472	1468	2940
Damodar Valley Corporation	10519	3328	13847
Sikkim	—9	11	2
	44376	18794	63172
Total (A+B+C+D)	148279	91819	240098

(X) Excluding two part billing, Andhra Pradesh Duty & Excise Duty & Cess.

2360. [*Transferred to the 18th December, 1992*]

Reduction in allocation for Power Projects in Andhra Pradesh

2361. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Electricity Authority/Rural Electrification Corporation have reduced allocation of funds under Rural Electrification Normal Programme from Rs. 9 crores to Rs. 1.40 crores to Andhra Pradesh; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI) : (a) and (b) On NABARD having agreed recently to provide funds for energisation of pumpsets under SPA Programme jointly funded by NABARD/Commercial Banks and REC, part of the funds under RE Normal Programme initially intended to be utilised for funding the pumset energisation programme solely by REC are now proposed to be utilised for the pumpset energisation under the participative SPA Programme so as to maximise the energisation of pumpsets in the State during the year. The revised total allocation for Andhra Pradesh, inclusive of Normal and SPA Programmes, will be Rs. 25 crores which will enable energisation of 48,000 pumpsets.

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समितियां

2362. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने ब्लाकों में ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समितियां काम कर रही हैं और केन्द्रीय सरकार ने इन समितियों के लिए कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) क्या इन समितियों के ब्लाकों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन समितियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले गांवों, जहां बिजली नहीं है, का कब तक विद्युतीकरण कर दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) इस समय, राजस्थान में केवल एक ग्राम विद्युतीकरण सहकारी सोसायटी कार्यरत है जोकि सवाईमाधोपुर जिले के टोडाभीम ब्लाक को कवर करती है । इस परियोजना के अन्तर्गत, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) द्वारा सोसायटी को ऋण के रूप में 97.30 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं और राजस्थान सरकार को 35 लाख रुपये प्रदान किए हैं ताकि उनके द्वारा सोसायटी की शेयर पूंजी में अंशदान किया जा सके । सोसायटी से प्राप्त सूचना के अनुसार, सोसायटी क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल सभी 148 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

Allocations for Koel-Karo Project

2363. SHRI INDER KUMAR GUJRAL : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have sanctioned only Rs. 5 crores this year for Koel-Karo hydel project; and

(b) if so, whether this allocation is considered sufficient for timely completion of the project ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAO) : (a) Out of the total budgetary support allocated by the Government to NHPC for 1992-93, NHPC had earmarked Rs. 5 crores for the Koel Karo Hydro-electric Project. However, the Planning Commission has recently agreed to allocation of an additional amount of Rs. 10 crores for this project in 1992-93.

(b) No, Sir. Timely completion of the project would depend upon availability of sufficient additional funds for the project during the 8th Plan.

रिहन्द जल विद्युत परियोजना में से मध्य प्रदेश के हिस्से को दिया जाना

2364. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश स्थित रिहन्द जल विद्युत परियोजना में मध्य प्रदेश का 15 प्रतिशत हिस्सा है और मध्य प्रदेश को कई वर्षों से यह हिस्सा नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ताकि मध्य प्रदेश को उसके हिस्से की बिजली मिल सके; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के हिस्से की बिजली का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश का कोई भुगतान किया है, यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) रिहन्द जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की परियोजना है । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत मध्य प्रदेश रिहन्द से उत्पादित विद्युत के 15% भाग का हिस्सेदार है जोकि साल-दर-साल ऊर्जा की उपलब्धता पर आधारित है । ऐसा न होने पर मुआवजा दिया जाता है । यह मुद्दा एक द्विपक्षीय मुद्दा है और किसी भी पार्टी ने केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की मांग नहीं की है ।

Standing Committee Report on Clearance of Power Projects

2365. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI :
SHRI V. GOPALSAMY :

Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether any report has been submitted by the High Power Standing Committee regarding clearance of the pending power projects; and